



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1939 (श0)

(सं० पटना 679) पटना, बृहस्पतिवार, 3 अगस्त 2017

सं० 17 स्कैनिंग(जमाबंदी पंजी)-88/2017-1060 (17)/रा०,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संकल्प

13 जुलाई 2017

विषय :- डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के अन्तर्गत राज्य के सभी अंचलों के जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटাইजेशन एवं संरक्षण करने के संबंध में।

राज्य के सभी 534 अंचलों में से अधिकांश अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजी आवश्यक नियमित रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। संधारित जमाबंदी पंजियाँ कतिपय स्थानों पर कई दशक पुराने हैं। अनेक स्थानों पर जमाबंदी पंजियों के कई पृष्ठों के गायब होने, जीर्ण-शीर्ण होने, अपठनीय होने, लिप्त-लेखन होने एवं अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है।

2. राजस्व प्रशासन का मूल आधार जमाबंदी पंजियाँ होती हैं। वर्तमान में सभी अंचलों में जमाबंदी पंजियाँ राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन रहती हैं, जिसकी अतिरिक्त प्रतियाँ अंचल कार्यालय एवं जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती हैं। जमाबंदी पंजियों के गायब होने, विवादस्पद लिप्त-लेखन होने, अपठनीय होने, क्षतिग्रस्त होने आदि की स्थिति में भूमि के स्वत्व निर्धारण, भूमि प्रमाण-पत्र निर्गत करने आदि में व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं जो राज्य में भूमि विवाद के मामलों का मुख्य कारण हैं।

3. केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के तहत राज्य के सभी अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजियों के स्कैनिंग, डिजिटাইजेशन एवं संरक्षण करने से राज्य में राजस्व प्रशासन का मूल अभिलेख का अद्यतनीकरण एवं भविष्य के लिए संरक्षण तथा लिप्त-लेखन की संभावना समाप्त करना संभव होगा। साथ ही भविष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कतिपय ऑनलाईन सेवाएँ राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराने, भूमि विवादों का निष्पादन करने, विशेष सर्वेक्षण कार्यों आदि में भी उपयोगिता होगी।

4. सरकार की डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के तहत प्राप्त की जानेवाली राशि का उपयोग करते हुए राज्य के सभी 534 अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटাইजेशन एवं संरक्षण किया जाय तथा इस कार्यक्रम के तहत आधारभूत संरचना का गठन, आवश्यक आधुनिक उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय एवं संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विवेक कुमार सिंह,

प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 679-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>